

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No.58/2017

No. E.678/O/Vol.VIII

Kolkata, Dated: 13/06/2017

All Concerned

(as per standard list)

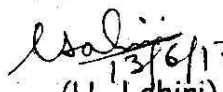
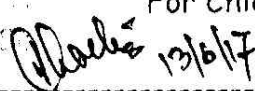
Sub: Introduction of Special Leave connected to inquiry of Sexual Harassment.

A copy of Railway Board's letter No. E(P&A)I-2017/CPC/LE-3 dated 29/05/2017 (RBE No. 51/2017) on the subject is forwarded herewith together with its enclosures, containing Advance Correction Slip (ACS) No.132 to IREC, Vol.I and Hindi version, for information, guidance, and necessary action.

In terms of the aforesaid instructions, special leave up to a period of 90 days may be granted to an aggrieved female Railway Servant on the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, during the pendency of inquiry under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the leave granted to the aggrieved female Railway Servant under this rule shall not be debited against the leave account.

This rule takes effect from the date, the notification was published by the Department of Personnel and Training viz. 15th March, 2017.

DA: As above.


(U. Ldhiri)
Dy. Chief Personnel Officer/R
For Chief Personnel Officer
 13/6/17 Phone no.: 24103

Index No. 1025: Special leave up to a period of 90 days may be granted to the aggrieved female Railway Servant connected to inquiry of Sexual Harassment and the leave so granted shall not be debited against the leave account.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBE No. 51/2017

No. E(P&A)I-2017/CPC/LE-3

New Delhi, dated 29.05.2017.

The General Managers and FA&CAOs,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Introduction of Special Leave connected to inquiry of Sexual Harassment.

Consequent upon the decision taken by the Government, the President is pleased to decide that the following rule may be inserted in the Railway Service (Liberalised Leave) Rules, 1949 in respect of female railway employees:-

Special Leave connected to inquiry of sexual harassment - Leave upto a period of 90 days may be granted to an aggrieved female Railway Servant on the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, during the pendency of inquiry under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the leave granted to the aggrieved female Railway Servant under this rule shall not be debited against the leave account.

2. This rule takes effect from the date, the notification was published by the Department of Personnel and Training viz. 15th March, 2017.

3. The provisions of the Railway Service (Liberalised Leave) Rules, 1949 are contained in Chapter-5 of Indian Railway Establishment Code (IREC), Volume-I, 1985 Edition (Reprint Edition-2008). In view of this, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that a new para 551(F) may be inserted in Chapter- 5 of the Indian Railway Establishment Code, Volume - I, 1985 Edition (Reprint Edition-2008) as per enclosed Advance Correction Slip No. 132.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

DA:- Correction Slip.


(Anil Kumar)

Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/CPC/LE-3

New Delhi, dated 29.05.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways

**ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE,
VOLUME-I, 1985 Edition- (THIRD REPRINT EDITION – 2008)**

Advance Correction Slip No. 132

The following new para 551 (F) may be inserted below 551 (E) in Chapter – 5 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 Edition (Reprint Edition – 2008):-

551(F):- Special Leave connected to inquiry of sexual harassment

Leave upto a period of 90 days may be granted to an aggrieved female Railway Servant on the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, during the pendency of inquiry under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the leave granted to the aggrieved female Railway Servant under this rule shall not be debited against the leave account.

(Authority: Railway Board's letter No. E(P&A)I-2017/CPC/LE-3 dated 29.05.2017)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पीएंडए)-2017/सीपीसी/एलई-3

नई दिल्ली, दिनांक 29.05.2017

महाप्रबंधक, विस एवं मुलेधि,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय:- यौन उत्पीड़न की जांच के संबंध में विशेष छुट्टी की शुरुआत.

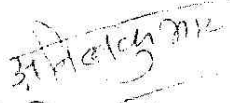
सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने एतद्वारा यह निर्णय लिया है कि महिला रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रेल सेवा (उदारीकृत छुट्टी) नियम, 1949 में निम्नलिखित नियम शामिल किया जाए.

यौन उत्पीड़न की जांच के संबंध में विशेष छुट्टी-कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम 2013 के तहत पीडित महिला रेलवे कर्मचारी को आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर जांच लंबित होने के दौरान 90 दिनों की अवधि तक की छुट्टी दी जाए जैसा भी मामला हो तथा इस नियम के तहत पीडित महिला रेलवे कर्मचारी को दी गई छुट्टी उसके छुट्टी के लेखे से डेबिट नहीं की जाए.

2. यह नियम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित की गई अधिसूचना की तारीख यथा 15.3.17 से लागू होगा.

3. रेल सेवा (उदारीकृत छुट्टी) नियम, 1949 के प्रावधान भारतीय रेल स्थापना संहिता (आईआरसीई) जिल्द-1 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण-2008) के अध्याय-5 में अंतर्विष्ट हैं. इसे देखते हुए संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-1 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण-2008) के अध्याय-5 में संलग्न अग्रिम संशोधन पर्ची सं 132 के अनुसार एक नया पैरा 551 (एफ) शामिल किया जाए.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालाय की सहमति से जारी किया जा रहा है.
5. कृपया पावती दें.


(अनिल कुमार)

उप निदेशक/ई(पीएंडए)-I
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पीएंडए)-I-2017/सीपीसी/एलई-3

नई दिल्ली, दिनांक 29.05.2017

प्रतिलिपि:- भारत के उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)



कृते वित्त आयुक्त/ रेलें

प्रतिलिपि:-

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 253 रेल भवन नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
2. महासचिव, एनएफआईआर कमरा नं. 236-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली. (60 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं. 256-ए रेल भवन, नई दिल्ली. (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
5. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन, कमरा नं. 402, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
6. अध्यक्ष, ग्रुप II अधिकारी एसोसिएशन, रेलवे बोर्ड
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 341-सी रेलवे बोर्ड
8. अध्यक्ष, भारतीय रेलवे ग्रुप II अधिकारी एसोसिएशन,
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप IV कर्मचारी संघ
11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- I 1985 संस्करण (तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण-2008) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.-----132

भारतीय रेल भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- I 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण-2008) के अध्याय-5 में 551(ई) के नीचे निम्नलिखित नए पैरा 551(एफ) शामिल किया जाए.

551(एफ):- यौन उत्पीड़न की जांच के संबंध में विशेष छुट्टी.

यौन उत्पीड़न की जांच के संबंध में विशेष छुट्टी-कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम 2013 के तहत पीड़ित महिला रेलवे कर्मचारी को आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर जांच लंबित होने के दौरान 90 दिनों की अवधि तक की छुट्टी दी जाए जैसा भी मामला हो तथा इस नियम के तहत पीड़ित महिला रेलवे कर्मचारी को दी गई छुट्टी उसके छुट्टी के लेखे से डेबिट नहीं की जाए.

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. सं.ई(पीएंडए)I-2017/सीपीसी/एलई-3 दिनांक 29.05.2017)